

**ALL INDIA LOCAL T. V. CHANNEL
OWNER'S WELFARE TRUST (R)**

**Head Office— 151-B, NEAR RAVI ICE FACTORY, ASHOK NAGAR,
BASHARATPUR, GORAKHPUR, (U.P.)**

Ref.No.- मेमो /2014

DATE:- 28-07-2014

श्री अग्नेश्वर सेन, ट्राई, सलाहकार
(बी एण्ड सी एस) नईदिल्ली

विषय :—टेलीकाम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र के संदर्भ में जारी परामर्श पत्र संख्या.07 / 2014, दिनांक 23-06-2014 पर आल इंडिया लोकल टी०वी० चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा दिये गये सुझावों के सन्दर्भ में :-

आदरणीय महोदय,

टेलीकाम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र के संदर्भ में परामर्श पत्र संख्या.07 / 2014, दिनांक 23-06-2014 को जारी करने के लिए आल इंडिया लोकल टी०वी० चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आप सभी को साधुवाद देते हुए अपने विचार प्रस्तुत कर लोकल टी०वी० चैनल के अस्तित्व के सम्बंध में महत्वपूर्ण बिन्दु ग्रहण करने का निवेदन कर रहा है।

महोदय, परामर्श पत्र का अवलोकन करने के उपरांत ऐसा विदित होता है कि इस परामर्श पत्र में लोकल टी०वी० चैनल के अस्तित्व को संज्ञान में नहीं लिया गया है। जबकि देश के सभी राज्यों के लगभग सभी जिलों में स्थानीय स्तर पर लोकल टी०वी० चैनल का प्रसारण होता है। यह लोकल टी०वी० चैनल का प्रसारण नॉन सेटेलाईट चैनल एवं जिलास्तर पर अपनी अलग आईडेंटिटी बरकरार रखते हुए डी०पी०ओ० / एम०एस०ओ० के प्लेटफार्म पर अपने कार्यक्रम का प्रसारण करता है। आपके संज्ञान में यह बिंदु लाना अत्यन्त आवश्यक है कि अलग-अलग राज्यों में पूर्व में कानून बनाकर लोकल टी०वी० चैनल के प्रसारण की लाईसेंसिंग की व्यवस्था है। यह लाईसेंस जिला प्रशासन द्वारा गहन छानबीन कर विज्ञापन एवं प्रोग्राम कोड को मद्देनजर रखते हुए नियम शर्तों एवं शुल्क के साथ दिये जाने की व्यवस्था चली आ रही है। उदाहरण के लिए, उ०प्र० में केबिल टी०वी० पर निजी चैनल के संचालन की अनुमति देते हुए तत्कालीन प्रमुख सचिव, उ०प्र०शासन, टी० जार्ज जोसेफ, ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को शासनादेश सं०-१७० दिनांक 16 फरवरी 2001 के माध्यम से निर्देश दिया था कि अग्रेतर निर्णय होने तक अतिरिक्त लाईसेंस फीस जमा न करने


संस्थापक/मुख्य द्रष्टव्य
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

के आधार पर लोकल टी०वी०चैनलों को संचालित करने पर केबिल आपरेटरों को प्रताड़ित न किया जाय। तभी से उत्तर प्रदेश में लोकल टी०वी०चैनलों का प्रसारण होता रहा है।

(दिनांक—16/02/2001 को जारी शासनादेश सं०.१७० की छाया प्रति संलग्न)

महोदय, वर्ष 2004 में भारत सरकार ने ट्राई एक्ट के प्रावधान में संशोधन करते हुए ब्राडकास्टिंग एवं केबिल सर्विसेज को दूरसंचार सेवाओं के रूप में अधिसूचित कर देने से अब प्रसारण एवं केबिल सर्विसेज का समस्त अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्र की सूची में सूचीबद्ध हो गया है।

अतः एम०आई०वी०/ट्राई का यह अधिकार है कि वह राज्यों के बजाय स्वयं लोकल टी०वी० चैनल के पंजीयन की व्यवस्था अलग से करें।

सम्भवतः यह महत्वपूर्ण पक्ष परामर्श पत्र में छूट गया है फिर भी आल इंडिया लोकल टी०वी० चैनल ऑनर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने इसी परिपेक्ष्य को ध्यान में रखकर आप द्वारा जारी परामर्श पत्र के सभी बिन्दुओं में लोकल टी०वी० चैनल से जुड़े विचार व विषय के अनुरूप उत्तर दिये हैं :—

बिन्दुवार सुझाव

1.3 :— डीएस वातावरण के संदर्भ में प्रदत्त विचार से आल इंडिया लोकल टी०वी० चैनल ऑनर्स वेलफेयर ट्रस्ट सहमत नहीं है। क्योंकि प्रसारण में प्रयुक्त तकनीकि (प्रणाली) आप्टिकल फाइबर केबिल में कम्प्यूनिकेशन का माध्यम टू वे है। लोकल टी०वी० चैनल /एल०सी०ओ० अपने प्रोग्राम को उसी आप्टिकल फाइबर केबिल के माध्यम से एम०एस०ओ० तक कूटबद्ध संकेतों को पहुँचा कर सभी चैनलों के साथ फीड में सम्मिलित हो सकता है। और डी०पी०ओ० पर ब्रॉडबैण्ड के माध्यम से प्रसारित कूटबद्ध संकेतों के रूप में भी शामिल किया जा सकता है।

1.4 :— पारम्परिक अर्थ में लोकल टी०वी० चैनल भी ब्राडकास्ट चैनल की श्रेणी में हैं, परन्तु यह टी०वी० प्रसारण के अलग रूप में विभेदित नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि लोकल टी०वी० चैनल का क्षेत्र जिलास्तर तक ही सीमित है और किसी भी दृष्टि से अन्य नियमित सेटेलाईट टी०वी० चैनल में किसी प्रकार से इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाता है।

1.5 :— लोकल टी०वी० चैनल का प्रसारण भी सामान्य टी०वी० चैनलों के अनुसार होता है जिसका वितरण का माध्यम डी०पी०ओ० (एम०एस०ओ०, हिंदू, आई०पी०टी०वी०) का प्लेटफार्म हो सकता है। डी०टी०एच० के प्लेटफार्म को छोड़कर क्योंकि लोकल टी०वी० चैनल का क्षेत्र जिलास्तर तक ही सीमित है।

1.6 :— यह परिभाषा सीमित है अतः आंशिक सहमति है। क्योंकि लोकल टी०वी० चैनल की परिभाषा इस बिंदु में अपरोक्ष रूप से समाहित है। इस कारण लोकल टी०वी० चैनल की एक अलग पहचान होना आवश्यक है।

1.7 :— सहमत हैं।

1.8 :— लोकल टी०वी० चैनल से इस प्रकार की गतिविधियों से कोई सम्बंध नहीं है।

1.9 :— कोई टिप्पणी नहीं।


28.7.2014

संस्थापक/मुख्य द्वारा
आल इंडिया लोकल टी०वी०
ऑनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

1.10 :— लोकल टी०वी० चैनल द्वारा अपलिंकिंग / डाउलिंकिंग जैसी कार्यप्रणाली का होना असम्भव है क्योंकि लाईसेंस / वितरण का क्षेत्र जिला स्तरीय ही होगा।

परामर्श के लिए दिये गये मुददों के सम्बंध में कहना है कि लोकल टी०वी०

चैनल में किसी भी प्रकार के एफ०डी०आई० की कोई सम्भावना नहीं है।

2.1.1 :— लोकल टी०वी० चैनल कर सकते हैं(समाहित कर सकते हैं) क्योंकि लोकल टी०वी० चैनल में किसी तरह का कोई एफ०डी०आई० नहीं होगा।

2.1.2 :— स्थानीय स्तर की राजनैतिक घटनाओं को प्रेषित या सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे स्थानीय निकाय, राजनैतिक बैठकें, रैलियां, राजनैतिक विचार गोष्ठियाँ एवं ऐसे ही अन्य कार्यकर्ताओं को प्रेषित या सम्मिलित कर सकते हैं।

2.1.3 :— सहमति है।

2.1.4 :— सहमति है।

2.1.5 :— से 2.2.6 तक कोई टिप्पणी नहीं।

3 :— लोकल टी०वी० चैनल नियमित टी०वी० प्रसारकों के क्षेत्र में अतिक्रमण कर ही नहीं कर सकता क्योंकि इसका विस्तार (भौगोलिक क्षेत्र) जिलास्तरीय ही है।

1.11 :— पी०एस० चैनलों में लोकल टी०वी० चैनल के श्रेणी के माध्यम से प्रेषित सामग्री, निर्धारित नियम, एवं शर्तों को अनुपालन सुनिश्चित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लोकल टी०वी० चैनल पर ही होगी अतः पंजीयन प्रक्रिया लोकल टी०वी० चैनल पर ही लागू होगी।

1.12 :— लोकल टी०वी० चैनल का पंजीयन भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक(आर०एन०आई०) जो एम०आई०बी० के अधीन संस्था है के नियमों के अनुरूप हो। और ऐसे में निजी/व्यक्तिगत/कम्पनी/ ट्रस्ट/सोसाईटी के रूप में पंजीकृत संस्था, लोकल टी०वी० चैनल के लाईसेंस हेतु अर्ह हो सकते हैं।

1.13 :— लोकल टी०वी० चैनल भी आई०पी०टी०वी० के साथ जुड़ सकता है।

1.14 :— लोकल टी०वी० चैनल भी एम०आई०बी० के दिशा निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र रूप से पंजीयन करायेगा।

1.15 :— सहमति है।

1.16 :— लोकल टी०वी० चैनल भी आवश्यकतानुसार कम्पनी एकट के तहत पंजीकृत हो सकते हैं।



28.7.2014
संस्थापक/मुख्य द्रस्ट
आर०एन०आई०बी०
ओनलैन वेलफेर ट्रस्ट

4:-कानूनी एकरूपता बनाये रखने के लिए सभी लोकल टी०वी० चैनल को अलग से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

1.17 :-

से

1.20 :- सहमति नहीं है। क्योंकि लोकल टी०वी० चैनल में किसी प्रकार की एफ०डी०आई० की गुंजाई/सम्मावना नहीं है।

5:- कोई विचार नहीं।

1.21 :- लोकल टी०वी० चैनल से कोई सम्बंध नहीं।

6:- लोकल टी०वी० चैनल पर लागू नहीं।

1.22 :- लोकल टी०वी० चैनल के संचालन/पंजीयन में जिला पुलिस एवं प्रशासन के माध्यम से एल०आई०य० द्वारा गोपनीय रिपोर्ट की व्यवस्था आवश्यक है।

7:- गोपनीय रिपोर्ट को ही सुरक्षा भंजूरी/शर्तों के रूप में स्वीकार किया जाए।

1.23 :- भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आर०एन०आई०) के नियमों के अनुसार जिला प्रशासन के रिपोर्ट के माध्यम से लोकल टी०वी० चैनल के शर्त, शुल्क आदि की व्यवस्थाएं समाचार पत्र/पत्रिका के समान किये जाने की अनुशंसा होनी चाहिए। जिसके परिचालन के क्षेत्र/भौगोलिक क्षेत्र जिला स्तरीय हो।

1.24 :- इसी प्रावधान के आलोक में ही आल इण्डिया लोकल टी०वी० चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने पूर्व में ही पंजीयन हेतु नियमावली बनाए जाने का प्रतिवेदन एम०आई०वी० एवं ट्राई को प्रेषित किया है।

1.25 :- पंजीयन आवश्यक है इसलिए केन्द्र सरकार (एम०आई०वी०) अपने स्तर तथा अलग से लोकल टी०वी० चैनल का पंजीयन कराने की व्यवस्था करे।

1.26 :- लोकल टी०वी० चैनल से सम्बंधित नहीं है।

1.27 :- लोकल टी०वी० चैनल का पंजीयन अलग से एम०आई०वी० द्वारा किया जाए तथा यह किसी डी०पी०ओ०/एम०एस०ओ० के अधीन न हो।

1.28 :- चूँकि स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयोजकत्व में जिला निगरानी समिति सभी प्रकार के प्रसारणों की निगरानी की जाती है ऐसे में किसी भी आपत्तिजनक कार्यक्रम/कन्टेन्ट के विरुद्ध लोकल टी०वी० चैनल के संचालक/स्वामी पर कड़ी कार्यवाही करने का प्रावधान उपलब्ध है।

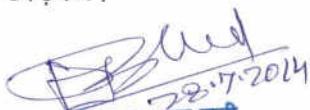
1.29 :- लोकल टी०वी० चैनल के पंजीयन की अवधि दस वर्ष निर्धारित हो।

1.30 :- लोकल टी०वी० चैनल के परिचालन का भौगोलिक क्षेत्र लाईसेंस/पंजीकरण के अनुमति के समय ही जिला स्तरीय हो।

1.31 :- लोकल टी०वी० चैनल पर लागू नहीं।


22.7.2014
संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

- 1.32 :— लोकल टी०वी० चैनल पर लागू नहीं।
- 8:— लोकल टी०वी० चैनल का पंजीयन एम०आई०बी० द्वारा आन लाईन किये जाने के सम्बंध में न्यूनतम रु० ५००/- वार्षिक के आधार पर १० वर्ष हेतु रु० ५०००/- निर्धारित किया जा सकता है।
- 9:— पिछले ट्रैक रिकार्ड के आधार पर लोकल टी०वी० चैनल को नवीनीकरण की व्यवस्था पंजीयन शुल्क लेकर होनी चाहिए।
- 10:— लोकल टी०वी० चैनल का भौगोलिक क्षेत्र जिला स्तरीय ही हो क्योंकि स्थानीय जनता को इससे लाभ होगा तथा उनकी समस्याओं एवं उसके निवारण आदि की दिशा में उन्हे सरकारी एवं प्रशासनिक सूचनाए़/जानकारी उपलब्ध हो सकेगी साथ ही स्थानीय बाजार गतिविधियाँ खेलकूद, बाढ़, मौसम, खेती बागवानी, स्वास्थ्य आदि जैसी जानकारियाँ भी स्थानीय स्तर पर उन्हे मुख्य धारा में लाने में सहायक सिद्ध होगी। चूंकि लोकल टी०वी० चैनल के प्रसारण का भौगोलिक क्षेत्र जिले की सीमा के अन्दर होगा इससे राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय चैनलों के क्षेत्र में अतिक्रमण की कोई भी स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं होगी।
- 1.33 :— मेंट्रोपोलिटन महानगरों क्षेत्र में २०, महानगरों पर १०, और छोटे शहरों में ६ लोकल टी०वी० चैनल के पंजीयन की सीमा होनी चाहिए।
- 1.34 :— डी०पी०ओ० को लोकल टी०वी० चैनल की संख्या के निर्धारण का अधिकार नहीं हो क्योंकि स्थानीय स्तर पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इसलिए एम०आई०बी० ही यह निर्णय ले।
- 11:— लोकल टी०वी० चैनल की संख्या निर्धारित होनी चाहिए परन्तु डी०पी०ओ० को यह अधिकार कदाचि नहीं दिया जाए वरन् इसका निर्णय एम०आई०बी० करे।
- 1.35 :— डी०पी०ओ० को कोई दायित्व लोकल टी०वी० चैनल के सम्बंध में न सौंपा जाये जिससे लोकल टी०वी० चैनल के अधिकारों का हनन हो। यह दायित्व पूर्णतया एम०आई०बी० एवं ट्राई के अधीन सुनिश्चित हो तथा समय—समय पर अन्य दिशा निर्देश जारी हो जिसका अनुपालन पूर्णतया लोकल टी०वी० चैनल करे और उसके प्रति लोकल टी०वी० चैनल ही जवाबदेय हो। बदली परिस्थिति में लोकल टी०वी० चैनल का प्रसारण एम०एस०ओ० के प्लेटफार्म, हिट्स के प्लेटफार्म, आई०पी०टी०वी० के प्लेटफार्म पर हो सकता है। जिस कारण इन्टरकनेक्शन होगा किन्तु प्रसारण का कन्टेन्ट एक ही व रीयल टाइम होगा। स्पष्ट हो कि लोकल टी०वी० चैनल का प्रसारण एक ही साथ सभी प्लेटफार्म पर होगा, मात्र डी०टी०एच० प्लेटफार्म को छोड़कर।
- 12:—
- 12.1:— सहमति है।



संस्थापक/मुख्य द्रष्टव्य
आल इण्डिया लॉकल टी०वी०
जॉनर्स वेलफेर इन्स्टी

28.7.2014

12.2:— असहमति है। क्योंकि भविष्य में इमजिंग टेक्नॉलॉजी आने से प्लेटफार्म शेयर होने की स्थिति रहेगी।

12.3:— सहमति है।

13:— डी०पी०ओ० पर बगैर एम०आई०बी० से लाईसेंस प्राप्त लोकल टी०वी० चैनल का प्रसारण करने हेतु रोक अवश्य हो।

1.36 :— लोकल टी०वी० चैनल पर लागू नहीं।

14 :— लोकल टी०वी० चैनल पर लागू नहीं।

1.37 :— लोकल टी०वी० चैनल के संदर्भ में डी०पी०ओ० को अधिकार नहीं होगा। क्योंकि इसकी मानीटरिंग केबल टी०वी०नेटवर्क रेग्युलेशन एक्ट/रूल्स के तहत गठित जिलास्तरीय निगरानी समिति द्वारा की जाने की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है।

1.38 :— लोकल टी०वी० चैनल के लिए भी पूर्व गठित जिलास्तरीय निगरानी समिति को यह दायित्व पूर्व से ही प्राप्त है। इस समिति द्वारा समय-समय पर कियाविधियों की निगरानी की जाती है। लोकल टी०वी० चैनल अपने कन्टेन्ट का रिकार्ड 90 दिन तक रखने में सक्षम है और आवश्यकतानुसार एम०आई०बी० एवं ट्राई के दिशा निर्देशों का पालन करता रहेगा।

1.39 :— इसके सभी बिन्दुओं से सहमति हैं। तथा लोकल टी०वी० चैनल को भी जिलास्तरीय निगरानी समिति के दायरे में रखा जाए।

1.40 :— डी०पी०ओ० के स्थान पर रिकार्ड रखने की जिम्मेदारी लोकल टी०वी० चैनल की हो क्योंकि लोकल टी०वी० चैनल अपना कन्ट्रोल रुम/स्टूडियो अलग स्थापित करता है जहाँ पर सारे रिकार्ड उपलब्ध रहेंगे। कोई भी सक्षम अधिकारी बिना पूर्व सूचना के भी इसकी जांच करने का अधिकृत हो सकता है।

15 :— लोकल टी०वी० चैनल के निगरानी हेतु पूर्व से ही जिलास्तरीय निगरानी समिति गठित है जिसके प्रावधानों के तहत लोकल टी०वी० चैनल के कार्यकर्ताओं की निगरानी के सम्बंध में समिति अपने सुझाव व निर्देश देकर जिला प्रशासन के सम्मुख रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वर्तमान में जो व्यवस्था लागू है उस समिति में जिला प्रशासन, पुलिस के अधिकारी, महिला महाविद्यालय की प्राचार्या, वरिष्ठ पत्रकार, बच्चों के मुद्रे पर कार्य करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता, मनोविज्ञान/सामाजिक विज्ञान विशेषज्ञ शामिल है। आल इंडिया लोकल टी०वी० चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट का मानना है कि इस समिति में लोकल टी०वी० चैनल के एक प्रतिनिधि को अवश्य शामिल किया जाय।

1.41 :— सभी प्रावधान से सहमति है परन्तु लोकल टी०वी० चैनल के संदर्भ में सम्पूर्ण दण्डात्मक कार्यवाही लोकल टी०वी० चैनल पर ही हो।

16 :— लोकल टी०वी० चैनल पर भी लागू हो।

1.42 :— लोकल टी०वी० चैनल के लिए इस विषय में अलग से प्रावधान हो जहाँ डी०पी०ओ० से किसी प्रकार का कोई सम्बंध न रहे क्योंकि पंजीयन आदि की प्रक्रिया एम०आई०बी० द्वारा ही सम्पादित हो।



28.7.2014

संस्थापक/मुख्य द्रष्टव्य
आल इंडिया लोकल टी०वी०
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

17 :— लोकल टी०वी० चैनल के सम्बंध/विषय में सम्पूर्ण अधिकार एम०आई०बी० को ही हो और वही नियमन एवं विनियमन से जुड़ी शर्तें बनाये। जिसका सुझाव उपरोक्त सभी बिन्दुओं में उद्धृत किया गया है।

1.43 :— कम से कम समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे निर्धारित नियमों का अनुपालन शीघ्रातिशीघ्र कर सके।

18 :— एम०आई०बी० द्वारा रजिस्टर्ड/पंजीकृत लोकल टी०वी० चैनल का ही प्रसारण प्रस्तावित विनियामक तंत्र के अनुरूप हो तथा इस हेतु अलग से एम०आई०बी० ही निर्णय ले।

19 :— 23 जून 2014 को जारी इस परामर्श पत्र के सभी बिन्दुओं के अध्ययन करने से यह प्रतीत होता है कि पूरे देश में चल रहे लोकल टी०वी० चैनल के विभिन्न मुद्दों को समाहित नहीं किया गया है। आल इंडिया लोकल टी०वी० चैनल ऑनर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने लोकल टी०वी० चैनल के अस्तित्व, इसके संरक्षण, इसके परिमार्जन, हित सम्बर्धन एवं विनियमन हेतु एम०आई०बी० एवं ट्राई को प्रस्ताव/पत्र दिनांक 11/08/2012 को पूर्व केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सुश्री अम्बिका सोनी जी, को इस संदर्भ में लिखा था जिसकी प्रतिलिपि ट्राई चेयरमैन डा० राहुल खुल्लर को भी भेजा था (पत्र की छाया प्रति संलग्न)। तदुपरांत दिनांक 30/09/2013 को भी केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, श्री मनीष तिवारी जी को इसी संदर्भ में एक पत्र लिखा था जिसमें सुश्री अम्बिका सोनी जी को लिखे पत्र का हवाला था। जिसकी प्रतिलिपि भी ट्राई चेयरमैन डा० राहुल खुल्लर को भी भेजा था (पत्र की छाया प्रति संलग्न)

जिसमें इस दिशा में हस्तक्षेप कर लोकल टी०वी० चैनल के विनियमन की मांग की है।

दिनांक 11/08/2012 एवं 30/09/2013 के पत्रों की छायाप्रति संलग्न।

आपके संज्ञान में यह बिन्दु लाना अति आवश्यक है कि, वर्तमान स्थिति में कई स्थानीय प्लेटफार्म के माध्यम से डी०पी०ओ०/एम०एस०ओ० अनाधिकृत रूप से एम०आई०बी० एवं ट्राई के दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए क्षेत्रीय प्रसारण करके विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोकल टी०वी० चैनल जो नान सेटेलाईट चैनल है और जिनका प्रसारण जिलास्तरीय है इनके


संस्थापक/मुख्य द्रष्टव्य
आल इंडिया लोकल टी०वी०
ऑनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

लिए भी ट्राई के परामर्श पत्र के अनुरूप आल इंडिया लोकल टी०वी० चैनल

ओनर्स वेलफेर ट्रस्ट ने अपने सुझाव बिंदुवार प्रस्तुत किये हैं जिनका गहन संज्ञान अत्यंत आवश्यक है। लोकल टी०वी० चैनल के लिए अलग से पंजीयन की व्यवस्था एवं एम०आई०बी० द्वारा समाचार पत्र/पत्रिकाओं के पंजीयन की नीति एवं नियम को जोड़कर लोकल टी०वी० चैनल का भी पंजीयन किया जा सकता है और यह प्रणाली सर्वग्राह्य एवं सुगम भी है। हमारा ऐसा मानना है कि बैर्झमानी का अवसर न प्राप्त हो तो सब ईमानदार हैं। इसी उद्देश्य से आल इंडिया लोकल टी०वी० चैनल ओनर्स वेलफेर ट्रस्ट ने भी लोकल टी०वी० चैनल के लाईसेंस हेतु जिलास्तरीय तक ही पंजीयन की आवश्यकता पर बल देते हुए एम०आई०बी० एवं ट्राई के सोच कि लोकल टी०वी० चैनल बिना किसी लाईसेंस के सेटेलाईट/क्षेत्रीय चैनलों की भाँति व्यवहार करते हैं। इसी बुनियाद के मद्देनजर लोकल टी०वी० चैनल ओनर्स वेलफेर ट्रस्ट का भी मानना है कि जब लाईसेंस जिलास्तरीय होगा तो उपयुक्त दोनों क्षेत्रों में अतिक्रमण की सम्भावना शून्य होगी।

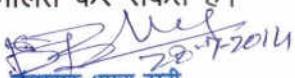
अध्याय-2

1:- पीएस की परिभाषा डी०पी०ओ० को केन्द्र बिन्दु में रख कर दी गई है। जबकि लोकल टी०वी० चैनल अपने कार्यक्रमों का निर्माण स्वयं करके अपने स्टूडियो/कन्ट्रोल रुम के माध्यम से ऑप्टिकल फाईबर केबल द्वारा एम०एस०ओ०/डी०पी०ओ० के प्लेटफार्म पर सभी चैनलों के साथ अपनी अलग आडेंटिटी के अनुरूप प्रसारित करते हैं। तथा लोकल टी०वी० चैनल के कार्यक्रम डाउलिंकिंग दिशा निर्देशों के अधीन अनुमति प्राप्त दूरदर्शन चैनल और सेटेलाईट टी०वी० चैनल समिलित नहीं होते हैं।

2.1.1 :- लोकल टी०वी० चैनल कर सकते हैं(समाहित कर सकते हैं) क्योंकि लोकल टी०वी० चैनल में किसी तरह का कोई एफ०डी०आई० नहीं होगा।

2.1.2 :- स्थानीय स्तर की राजनैतिक घटनाओं को प्रेषित या समिलित कर सकते हैं, जैसे स्थानीय निकाय, राजनैतिक बैठकें, रैलियां, राजनैतिक विचार गोष्ठियाँ एवं ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों को प्रेषित या समिलित कर सकते हैं।

2.1.3 :- सहमति है।


28.7.2014
संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी
आल इंडिया लोकल टी०वी०
ओनर्स वेलफेर ट्रस्ट

2.1.4 :— सहमति है।

2.1.5 :— से 2.2.6 तक कोई टिप्पणी नहीं।

3 :— लोकल टी०वी० चैनल नियमित टी०वी० प्रसारकों के क्षेत्र में अतिक्रमण कर ही नहीं कर सकता क्योंकि इसका विस्तार (भौगोलिक क्षेत्र) जिलास्तरीय ही है।

4 :— कानूनी एकरूपता बनाये रखने के लिए सभी लोकल टी०वी० चैनल को अलग से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

5.— लोकल टी०वी० चैनल कोई विचार न हो यानि किसी भी प्रकार की एफ०डी०आई० की अनुमति न हो।

6.— लोकल टी०वी० चैनल पर लागू नहीं।

7.— गोपनीय रिपोर्ट को ही सुरक्षा मंजूरी / शर्तों के रूप में स्वीकार किया जाए।

8.— लोकल टी०वी० चैनल का पंजीयन एम०आई०बी० द्वारा आन लाईन किये जाने के सम्बंध में न्यूनतम रु० 500/- वार्षिक के आधार पर 10 वर्ष हेतु रु० 5000/- निर्धारित किया जा सकता है।

9.— पिछले ट्रैक रिकार्ड के आधार पर लोकल टी०वी० चैनल को नवीनीकरण की व्यवस्था पंजीयन शुल्क लेकर होनी चाहिए।

10.— लोकल टी०वी० चैनल का भौगोलिक क्षेत्र जिला स्तरीय ही हो क्योंकि स्थानीय जनता को इससे लाभ होगा तथा उनकी समस्याओं एवं उसके निवारण आदि की दिशा में उन्हे सरकारी एवं प्रशासनिक सूचनाएँ/जानकारी उपलब्ध हो सकेगी साथ ही स्थानीय बाजार गतिविधियाँ खेलकूद, बाढ़, मौसम, खेती बागवानी, स्वास्थ्य आदि जैसी जानकारियां भी स्थानीय स्तर पर उन्हे मुख्य धारा में लाने में सहायक सिद्ध होगी। चूंकि लोकल टी०वी० चैनल के प्रसारण का भौगोलिक क्षेत्र जिले की सीमा के अन्दर होगा इससे राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय चैनलों के क्षेत्र में अतिक्रमण की कोई भी स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं होगी।

11.— लोकल टी०वी० चैनल की संख्या निर्धारित होनी चाहिए परन्तु डी०पी०ओ० को यह अधिकार कदापि नहीं दिया जाए वरन् इसका निर्णय एम०आई०बी० करे।

संस्थापक/मुख्य द्रष्टव्य
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ऑनस्टेट वेलफेर द्रष्टव्य

12:-

12.1:- सहमति है।

12.2:- असहमति है। क्योंकि भविष्य में इर्मजिंग टेक्नॉलाजी आने से प्लेटफार्म शेयर होने की स्थिति रहेगी।

12.3:- सहमति है।

13:- डी०पी०ओ० पर बगैर एम०आई०बी० से लाईसेंस प्राप्त लोकल टी०बी० चैनल का प्रसारण करने हेतु रोक अवश्य हो।

14 :- लोकल टी०बी० चैनल पर लागू नहीं।

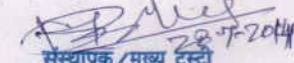
15 :- लोकल टी०बी० चैनल के निगरानी हेतु पूर्व से ही जिलास्तरीय निगरानी समिति गठित है जिसके प्रावधानों के तहत लोकल टी०बी० चैनल के कार्यकर्मों की निगरानी के सम्बंध में समिति अपने सुझाव व निर्देश देकर जिला प्रशासन के सम्मुख रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वर्तमान में जो व्यवस्था लागू है उस समिति में जिला प्रशासन, पुलिस के अधिकारी, महिला महाविद्यालय की प्राचार्या, वरिष्ठ पत्रकार, बच्चों के मुद्रे पर कार्य करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता, मनोविज्ञान/सामाजिक विज्ञान विशेषज्ञ शामिल है। आल इंडिया लोकल टी०बी० चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट का मानना है कि इस समिति में लोकल टी०बी० चैनल के एक प्रतिनिधि को अवश्य शामिल किया जाय।

16 :- लोकल टी०बी० चैनल पर भी लागू हो।

17 :- लोकल टी०बी० चैनल के सम्बंध/विषय में सम्पूर्ण अधिकार एम०आई०बी० को ही हो और वही नियमन एवं विनियमन से जुड़ी शर्तें बनाये। जिसका सुझाव उपरोक्त सभी बिन्दुओं में उद्धृत किया गया है।

18 :- एम०आई०बी० द्वारा रजिस्टर्ड/पंजीकृत लोकल टी०बी० चैनल का ही प्रसारण प्रस्तावित विनियामक तंत्र के अनुरूप हो तथा इस हेतु अलग से एम०आई०बी० ही निर्णय ले।

19 :- 23 जून 2014 को जारी इस परामर्श पत्र के सभी बिन्दुओं के अध्ययन करने से यह प्रतीत होता है कि पूरे देश में चल रहे लोकल टी०बी० चैनल के विभिन्न मुद्राओं को समाहित नहीं किया गया है। आल इंडिया लोकल टी०बी० चैनल ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने लोकल टी०बी० चैनल के अस्तित्व, इसके संरक्षण, इसके परिमार्जन, हित सम्बर्धन एवं विनियमन हेतु एम०आई०बी० एवं द्वाई


संस्थापक/मुख्य द्रष्टा
आल इंडिया लोकल टी०बी०
ओनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

को प्रस्ताव/पत्र दिनांक 11/08/2012 को पूर्व केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुश्री अम्बिका सोनी जी, को इस संदर्भ में लिखा था जिसकी प्रतिलिपि द्राई चेयरमैन डा० राहुल खुल्लर को भी भेजा था (पत्र की छाया प्रति संलग्न)। तदुपरांत दिनांक 30/09/2013 को भी केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, श्री मनीष तिवारी जी को इसी संदर्भ में एक पत्र लिखा था जिसमें सुश्री अम्बिका सोनी जी को लिखे पत्र का हवाला था। जिसकी प्रतिलिपि भी द्राई चेयरमैन डा० राहुल खुल्लर को भी भेजा था (पत्र की छाया प्रति संलग्न) जिसमें इस दिशा में हस्तक्षेप कर लोकल टी०वी० चैनल के विनियमन की मांग की है।

दिनांक 11/08/2012 एवं 30/09/2013 के पत्रों की छायाप्रति संलग्न।

आपके संज्ञान में यह बिन्दु लाना अति आवश्यक है कि वर्तमान स्थिति में कई स्थानीय प्लेटफार्म के माध्यम से डी०पी०ओ०/एम०एस०ओ० अनाधिकृत रूप से एम०आई०बी० एवं द्राई के दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए लोकल टी०वी० चैनल का क्षेत्रीय प्रसारण करके विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोकल टी०वी० चैनल जो नान सेटेलाईट चैनल है और जिनका प्रसारण जिलास्तरीय है इनके लिए भी द्राई के परामर्श पत्र के अनुरूप आल इंडिया लोकल टी०वी० चैनल ऑनर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने अपने सुझाव बिंदुवार प्रस्तुत किये हैं जिनका गहन संज्ञान अत्यंत आवश्यक है। लोकल टी०वी० चैनल के लिए अलग से पंजीयन की व्यवस्था एवं एम०आई०बी० द्वारा समाचार पत्र/पत्रिकाओं के पंजीयन की नीति एवं नियम को जोड़कर लोकल टी०वी० चैनल का भी पंजीयन किया जा सकता है और यह प्रणाली सर्वग्राह्य एवं सुगम भी है। हमारा ऐसा मानना है कि बेर्मानी का अवसर न प्राप्त हो तो सब इमानदार हैं। इसी उद्देश्य से आल इंडिया लोकल टी०वी० चैनल ऑनर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने भी लोकल टी०वी० चैनल के लाईसेंस हेतु जिलास्तरीय तक ही पंजीयन की आवश्यकता पर बल देते हुए एम०आई०बी० एवं द्राई के सोच कि लोकल टी०वी० चैनल बिना किसी लाईसेंस के सेटेलाईट/क्षेत्रीय चैनलों की भाँति व्यवहार करते हैं। इसी बुनियाद के मद्देनजर लोकल टी०वी० चैनल


22.7.2014
संस्थापक/मुख्य प्रस्तोता
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ऑनर्स वेलफेयर ट्रस्ट

(12)

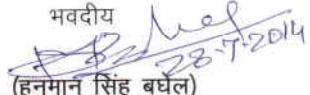
ओनर्स वेलफेर ट्रस्ट का भी मानना है कि जब लाईसेंस जिलास्तरीय होगा तो उपयुक्त दोनों क्षेत्रों में अतिकमण की सम्भावना शून्य होगी।

महोदय, सभी लोकल टी०वी० चैनल में बड़ी संख्या में टेक्नीशियन, कैमरापरशन / वीडियो जर्नलिस्ट एवं मीडियाकर्मी के अलावा कई कार्यक्रम तैयार करने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं। यदि ऐसे में लोकल टी०वी० चैनल के लिए अलग से नियमावली नहीं बनती है तो स्थिति चिन्तनीय होगी और स्थानीय स्तर पर आम जनता को सूचना के अधिकार, जानकारियां, सूचनाएं आदि से बंचित होना पड़ेगा और बड़ी संख्या में देश का एक बड़ा प्रशिक्षित वर्ग बेरोजगार हो जायेगा।

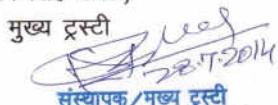
हम आजीवन आपके कृतज्ञ रहेंगे।

धन्यवाद! सादर

भवदीय


(हनुमान सिंह बघल)

मुख्य द्रस्टी


संस्थापक/मुख्य द्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ओनर्स वेलफेर ट्रस्ट

संलग्न -

1. तत्कालीन प्रमुख सचिव, उ०प्र०शासन,
टी० जार्ज जोसेफ, द्वारा दिनांक-16/02/2001 को
निर्गत शासनादेश की छाया प्रति संलग्न।

- 2- दिनांक 11/08/2012 एवं
30/09/2013 के पत्रों की छायाप्रति संलग्न।


संस्थापक/मुख्य द्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ओनर्स वेलफेर ट्रस्ट

संख्या-१७०/११-क. नि. -६-२००१, तदनिकांक
१४.८.११

प्रधान,

टो० वार्ज बोसेप,

प्रभुब सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

मंत्री,

सभस्त जिला माइस्ट्रेट,

उत्तर प्रदेश।

२२ अंक १८८८पन ग्रन्थाग-६

लेखन दिनांक १६ फरवरी, २००१

मिप्प: केबिल आपरेटरों द्वारा अपने स्वयं के ऐनल घलाकर वो डिपो प्रदर्शन करते हुये फ़िल्मों, न्यूज इत्यादि दिखाने पर लाइसेंस फोस को देता तथा विद्यापन प्रसारित किये जाने, तो सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोगों पंजीकृत केबिल आपरेटर नियमोंनुसार सेटेलाइट ऐनलों के कार्यक्रम प्रसारित इर सकते हैं, जिस पर उन्हें मनोरंजन ठर भी अद्वा लगना हींगा। यदि केबिल आपरेटर अपना स्वयं का ऐनल घलाकर उसमें वो डिपो प्रदर्शन करते हुये प्रसारित व कामोराइट वालों हो फ़िल्मों, न्यूज इत्यादि दिखाना चाहते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश वो डिपो नियमावलों के समर्पित लाइसेंस गो प्राप्त लगना होगा। जिसके लिए लम्ब-सम्ब हो २४००/-प्रति लाइसेंस फोस जाए तराये जाने तथा इस सम्बन्ध में उ०५० वो डिपो नियमावलों में आवश्यक व्यवस्था किये जाने पर विद्यार लिया जा रहा है। अतः यह निर्देशित ०५० जाता है कि इस सम्बन्ध में अग्रेटर निर्णय दोने तक अतिरिक्त लाइसेंस फोस लगने के आधार पर केबिल आपरेटरों को प्रताङ्कित न लिया जाए।

२- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि केबिल आपरेटर भारत सरकार द्वारा लागू विद्यापन लोड के अन्तर्गत सेटेलाइट ऐनलों पर यह रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत लाइसेंस प्रसारित गहों कर सकते हैं और अपने लोडल ऐनलों पर भी विद्यापन लाइसेंस लोड के ग्रन्थार हो कर लक्षते हैं।

महोदय,

॥ टो० वार्ज बोसेप ॥

प्रभुब सचिव।

८

संख्या-१७०/११/११-क. नि. -६-२००१, तदनिकांक।

अतिलिपि, मनोरंजन कर आयुक्त, उ०५० लखनऊ हो सूचनार्थ एवं आक्षयक आधारही हेतु प्रेषित।

आया है,

॥ दूरदृश्य बोहान ॥

विद्युत सचिव।

८

Mo.9235560283

**ALL INDIA LOCAL T. V. CHANNEL
OWNER'S WELFARE TRUST (R)**

**Head Office — 151-B, NEAR RAVI ICE FACTORY, ASHOK NAGAR,
BASHARATPUR, GORAKHPUR, (U.P.)**

DATE-11 - 08 -2012

Ref.No.- सेमो /2012

सेवा में,

सुश्री अम्बिका सोनी जी,

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री

भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय -- लोकल टीवी०चैनलों को विनियमित करने तथा पंजीयन के संबन्ध में स्पष्ट
नियमावली जारी करने के संदर्भ में -

महोदया,

लोकल टी०वी०चैनल, शासन और प्रशासन की नीतियों को आम जन तक पहुँचाने के साथ

क्षेत्रीय जनता को उनकी समस्याओं और आस-पास की गतिविधियों, कार्यक्रमों और

स्थानीय समाचारों को स्थानीय स्तर पर एम०एस०ओ० के प्लेटफार्म से सभी चैनलों के

साथ अपने कार्यक्रमों को स्थानीय एम०एस०ओ० के माध्यम से प्रसारित करता रहा है।

महोदया, लोकल टी०वी०चैनल (केबिल टेलीवीजन नेटवर्क) रूल्स 1994 एवं (केबिल

टेलीवीजन नेटवर्क) एक्ट 1995 की परिमाणा (2) (जी) एवं स्टैन्डर्ड्स आफ क्वालिटी आफ

सेवाएँ/गुण्य इस्टी
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ओनसे बेलफेयर इस्ट

सर्विस(ब्राडकास्टिंग एण्ड केबिल सर्विसेज)(केबिलटेलीविजन- कैस एरियाज)रेगुलेशन,2006

की परिभाषा (2) (ओ) तथा स्टैन्डर्ड्स आफ क्वालिटी आफ सर्विस (ब्राडकास्टिंग एण्ड

केबिल सर्विसेज)(केबिलटेलीविजन -नान कैस एरियाज)रेगुलेशन,2009 की परिभाषा

(2)(यस)के तहत प्रोग्रामिंग सर्विस के रूप में सम्पूर्ण टेलीवीजन ब्राडकास्ट का अधिकार

टेलीवीजन नेटवर्क को प्राप्त है। इस धारा के तहत सभी स्थानीय टीवी चैनल पंजीकृत

किये जाते हैं । केन्द्र सरकार द्वारा पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग में 500/- रुपया प्रति

वर्ष पंजीयन शुल्क के रूप में अनकलासीफाईड रीसीट्स हेड में जमा कराये जाने की

अनिवार्यता है ।

□ महोदया, चूंकि देश के अलग - अलग राज्यों में लोकल टी0वी0चैनलों के पंजीयन का

भी प्रावधान है। इसी के निमित्त में लोकल टी0वी0चैनलों को पंजीकृत कराना भी

अनिवार्य है ।

□ महोदया, केन्द्र सरकार द्वारा लोकल टी0वी0चैनलों के पंजीयन के लिए अभी तक कोई

स्पष्ट नियमावली अथवा गाईड लाइन न होने के कारण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा

समय - समय पर उत्पन्न बाधाओं और व्यवधान के कारण लोकल टी0वी0चैनल का

शोषण एवं उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में लोकल टी0वी0चैनल के अस्तित्व पर प्रहार

होना स्वाभाविक है ।

□ महोदया, वर्तमान समय में आपके मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण देश में वर्ष 2014 तक

डिजिटलाइजेशन के प्रक्रिया को पूरा कराना है, साथ ही ट्राई के नियमों का भी

अनुपालन होना है। ऐसी स्थिति में ट्राई के नियमावली तथा दिशा निर्देशों में लोकल

टी0वी0चैनल को समाहित करना समीचीन होगा । आपसे कर बढ़ प्रार्थना है कि इस

सम्बन्ध में ट्राई के नियमों में लोकल टी0वी0चैनल को भी शामिल करते हुए अलग संख्या 11-8-2012

संस्थापक/प्रब्ल ट्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी0वी0
ओनर्स वेलफेर प्रस्त

लोकल टी०वी०चैनलों के लिए नियमावली बनाया जाना आवश्यक है। जिसमें लोकल टी०वी०चैनलों के प्रसारण एवं रेगुलेशन की अलग से स्पष्ट व्याख्या हो।
 महोदया, हमें आशा है कि आप अपने स्तर से अपने मंत्रालय के माध्यम से इस सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए लोकल टी०वी०चैनल के अस्तित्व व विकास के लिए दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करेंगी।

इसी विश्वास के साथ ।

सादर ।

घन्यवाद!

भवदीय

BSNL
11-8-2012
(हनुमान सिंह बघेल)

प्रतिलिपि -

मुख्य / संस्थापक द्रस्टी

1. डा० राहुल खुल्लर, ड्राई चेयरमैन,
 नईदिल्ली, को आवश्यक कार्यवाही
 हेतु प्रेषित ।

BSNL
11-8-2012
संस्थापक / मुख्य द्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ओनसे वेलफेयर द्रस्ट



Mo.9235560283

ALL INDIA LOCAL T. V. CHANNEL
OWNER'S WELFARE TRUST (R)

Head Office— 151-B, NEAR RAVI ICE FACTORY, ASHOK NAGAR,
BASHARATPUR, GORAKHPUR , (U.P.)

Ref.No.- मेमो /2013

DATE-30 - 09 -2013

सेवा में,

श्री मनीष तिवारी जी,

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री

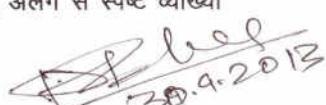
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय -- लोकल टीवी०चैनलों को विनियमित करने तथा पंजीयन के संबन्ध में स्पष्ट नियमावली जारी करने के संदर्भ में -

महोदय,

लोकल टी०वी०चैनल, शासन और प्रशासन की नीतियों को आम जन तक पहुँचाने के साथ क्षेत्रीय जनता को उनकी समस्याओं और आस-पास की गतिविधियों, कार्यक्रमों और स्थानीय समाचारों को स्थानीय स्तर पर एम०एस०ओ० के प्लेटफार्म से सभी चैनलों के साथ अपने कार्यक्रमों को प्रसारित करता रहा है।

द्वाई द्वारा लोकल टी०वी०चैनलों के प्रसारण एवं रेगुलेशन की अलग से स्पष्ट व्याख्या अति आवश्यक है।


30.9.2013

संस्थापक/मूल्य द्रस्टी
आल इण्डिया लोकल टी०वी०
ऑनर्स बेलफेयर ट्रस्ट

2.

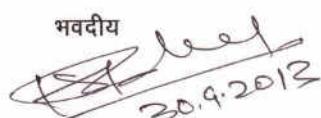
महोदय, हमने दिनांक 11/08/2012 को पूर्व केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सुश्री अम्बिका सोनी जी, को इस संदर्भ में एक पत्र लिखा था जिसकी प्रतिलिपि ट्राई चेयरमैन डा० राहुल खुल्लर को भी भेजा था (पत्र की छाया प्रति संलग्न)। जनवरी 2013 में कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से यह पता चला कि आपके मंत्रालय ने लोकल टी०वी० चैनलों के संदर्भ में ट्राई से सुझाव मांगे हैं किन्तु कोई आधिकारिक सूचना न तो हमें मिली न ही अब तक हुई किसी कार्यवाही से ही हम अवगत हैं।

महोदय, हमें आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप अपने स्तर से अपने मंत्रालय के माध्यम से इस सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए लोकल टी०वी०चैनलों के अस्तित्व व विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की कृपा कर हमें अनुग्रहीत करने की कृपा करेंगे।

सादर।

धन्यवाद!

भवदीय


30.9.2013
(हनुमान सिंह बघेल)

प्रतिलिपि -

डा० राहुल खुल्लर, ट्राई चेयरमैन,
नईदिल्ली, को आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित।

संलग्न—

दिनांक 11/08/2012 के पत्र की
छायाप्रति।

मुख्य/संस्थापक ट्रस्टी

